क्या मुफ्त, अनिवार्य शिक्षा असम्भव है?

ज़्यां ड्रेज़

किसी ने सुझाव दिया था कि भारत प्राथमिक शिक्षा को मूलभूत अधिकार घोषित करके अपनी आज़ादी की पचासवीं सालगिरह मना सकता है। पहले तो इस प्रस्ताव की भरपूर प्रशंसा की गई और फिर इसे ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया। संसद ने स्वर्ण जयंती का जश्न अनगिनत भाषणों के साथ मनाना पसन्द किया था। इस स्थिति ने मुझे एक दुकान में रखे एक सेकण्ड हैण्ड टी.वी. पर लगे लेबल की याद दिला दी थी : 'सिर्फ आवाज़'।

शिक्षा को बुनियादी अधिकार बनाने सम्बंधी संविधान संशोधन विधेयक काफी लम्बे समय से धूल खाने के बाद बढ़ते जन दबाव के कारण अब संसद में प्रस्तुत होनेवाला है। किन्तु वास्तविक चुनौती तो इस संशोधन पर अमल करने की है। इस संशोधन के वित्तीय निहितार्थ से निपटना इस चुनौती का सबसे अहम पहलू नहीं है। कहा जा रहा है कि सरकार का फंसाव तीन परस्पर विरोधी प्राथमिकताओं की वजह से था : चुनिंदा राजकोषीय अनुशासन, शिक्षकों का उदार वेतन और शिक्षा का बुनियादी अधिकार।

पहली प्राथमिकता चुनिंदा राजकोषीय अनुशासन की है। इसमें 'चुनिंदा' शब्द बहुत अहमियत रखता है क्योंकि सामान्य राजकोषीय अनुशासन के लिए तो ऐसे कदम उठाना होंगे जो वर्तमान स्वीकार्य सीमाओं से परे हैं। जैसे सम्पन्न वर्ग को मिल रही सब्सिडी में कटौती, फौजी खर्च में कटौती और आयकर में भारी वृद्धि। ये ऐसे उपाय हैं जो शक्तिशाली खेमों के विरुद्ध जाएंगे और इसलिए अक्सर ऐसे उपाय नहीं किए जाते। इनकी बजाय राजकोषीय अनुशासन की तलवार कमज़ोर लक्ष्यों पर ही भांजी जाती है।

इस बात पर भी विवाद हो सकता है कि वास्तव में राजकोषीय अनुशासन कितना महत्व रखता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) अर्थशास्त्र पाठशाला के शिष्यों के लिए तो राजकोषीय अनुशासन वेदवाक्य बन गया है। इस नुस्खे को इस आधार पर उचित बताया जाता है कि मुद्रास्फीति को रोकने के लिए यह ज़रूरी है। किन्तु यह शायद ही कभी बताया जाता हो कि मुद्रास्फीति को इतना भयानक दैत्य क्यों माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तकें इस विषय पर प्रायः मौन ही रहती हैं। फ्रैन्स हॉन ने 15 वर्ष पूर्व अपनी विख्यात पुस्तक 'मनी एण्ड इन्फ्लेशन' में मुद्रास्फीति को अपने आप में एक खराबी मानने के बारे में यह टिप्पणी की थी, 'यह एक ऐसी धारणा है जिसका खुलासा मानवशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों को करना होगा - अर्थशास्त्री कोई मदद नहीं कर सकते।'

मुद्रास्फीति चुनौती नहीं है

गलतफहमी से बचने के लिए मैं यह स्पष्ट कर दूं कि अर्थशास्त्री मुद्रास्फीति से क्या समझते हैं। उनके अनुसार मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब समय के साथ कीमतें तथा पारिश्रमिक बढ़ रहे हों। यह उस स्थिति से अलग है जब कीमतें तो बढ़ रही हों किन्तु पारिश्रमिक नहीं। यह दूसरी स्थिति साफ तौर पर अवांछनीय है और लोग इसका विरोध ठीक ही करते हैं। किन्तु यहां परिभाषित रूप में मुद्रास्फीति कोई खराब चीज़ हो, यह ज़रूरी नहीं है।

मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब कीमतें तथा पारिश्रमिक बढ़ रहे हों। यह उस स्थिति से अलग है जब कीमतें तो बढ़ रही हों किन्तु पारिश्रमिक नहीं। यह दूसरी स्थिति साफ तौर पर अवांछनीय है और लोग इसका विरोध ठीक ही करते हैं। किन्तु यहां परिभाषित रूप में मुद्रास्फीति कोई खराब चीज़ हो, यह ज़रूरी नहीं है।